TEST CODE	8	1	2	4	1	0

MGP 2025

Time Allowed : Three Hours
समय : तीन घंटे

Maximum Marks : 250
अधिकतम अंक : 250

GENERAL STUDIES / सामान्य अध्ययन

Name Of Candidate परीक्षार्थी का नाम	TESHUKANT		
Roll No./अनुक्रमांक	1910189032	Medium/माध्यम	English ☐ हिंदी ☑
Center Code/परीक्षा केंद्र	mukherjeenagar	Date/दिनांक	22/07/25

*Center Code : For Online - 1900 / Delhi : Karol bagh - 1901, ORN - 1902, Mukharji Nagar - 1903 / Patna : Boring Rd. - 2001 / Hyderabad : Jawahar Nagar - 2101

INDEX TABLE / अनुक्रमणिका

Q. No. प्र.सं.	Max. Marks अधिकतम अंक	Marks Obtained प्राप्तांक
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Total/कुल अंक	250	

Examiner's Discretion/मूल्यांकन कर्ता का विवेक :

Total Marks/कुल अंक :

*Examiner's Discretion is the marks awarded at the discretion of the examiner based on your overall impression, on the basis of (but not limited to) your handwriting, presentation, use of diagrams, flowcharts, facts and figures or absolutely anything that he/she liked in your copy.

मूल्यांकन कर्ता का विवेक अंक, आपकी लिखावट, प्रस्तुति, आरेखों के उपयोग, फ़्लोचार्ट, तथ्यों और आंकड़ों या समग्र रूप किसी अन्य विषय वस्तु, जो मूल्यांकन कर्ता को आपकी कॉपी में पसंद आयी के आधार पर (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) पर दिए गए अंक हैं।

INSTRUCTION / अनुदेश

1. Please do furnish Name, Email, Roll No and Mobile in the answer sheet.
कृपया उत्तर–पुस्तिका में नाम, ईमेल, रोल नंबर और मोबाइल नंबर भरें।

2. There are **TWENTY** questions printed in ENGLISH & HINDI, all questions are compulsory.
उत्तर पुस्तिका में अंग्रेजी/हिंदी में बीस प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए निर्धारित अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं।

4. Answers must be written in the medium authorized in the admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided.
उत्तर प्रवेश पत्र में अधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जो कि दिए गए स्थान में इस प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के कवर पर स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।

5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum Answer Booklet must be clearly Struck off.
प्रश्नों में शब्द सीमा, यदि निर्दिष्ट हो, का पालन किया जाए। प्रश्न–सह–उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गये किसी भी पृष्ठ या पृष्ठ के भाग को स्पष्ट रूप से काट दें।

For Student Only / केवल परीक्षार्थी प्रयोग हेतु

Start Time/प्रारंभ करने का समय :	End Time/समाप्त करने का समय :
9:47	12:50
Mode Of Examination/ परीक्षा की विधि :	Online/ऑनलाइन ☐ Offline/ऑफलाइन ☑

For Office Use Only / केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

ECN CODE/ ईसीएन कोड :	EG/ईजी :	Evaluation Date/ मूल्यांकन तिथि :
	① ② ③ ④ ⑤	

Note: Students are expected to incorporate suggestions from the feedback provided in the answers. Discussion classes for the tests are also available online in your portal to aid in your preparation. Further, students are requested to see the good copies of the tests and learn from them. You can also discuss your copy with a Mentor and discover ways and means to improve your answers, or if you have any issues with this test / copy. Ask specific questions, to get specific answers.

EXAMINER'S REMARKS

ForumIAS

CRITERIA FOR THE FEEDBACK SECTION AT THE END OF EACH QUESTION

1. **AWIS = Answered What is Asked.** This means whether you have addressed the core demand of the question or not. Addressing the core demand of the question gets you an objectively fair score. It is examiner's perception if you have understood the question and if you know the answer in the first place. Creative answer writing, sometimes missing the core demand, may fetch very high or very low scores, and exposes your answer to the subjectivity of the examiner.
2. **CD & VA = Content Density & Value Addition.** Examiner will evaluate the quality and quantity of your content in the answer. In the same word limit and space limit have you (a) written what is asked (b) gone beyond what is asked (c) enriched answers through combination of (but not all!) suggestions, ideas, quotes, flowcharts, diagrams, facts and figures, data etc. This affects objective components of assessment.
3. **S & F = Structure & Flow** = Whether you have structured your answer properly or not. Whether the answer has been broken into parts and sub-parts and each part has been addressed appropriately or not. Whether the flow of the answer is maintained. Affects both subjective and objective components of assessment.
4. **P & R** = How your answer performs on the criteria of **presentation, ease of read, clarity and apparent effort** in writing the answer. This affects the subjective components of assessment.

ForumIAS

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

Q.1) "Extraordinary powers must be exercised with extraordinary care." Discuss in the context of Article 142 of the Indian Constitution. (10 marks, 150 words)

"असाधारण शक्तियों का प्रयोग असाधारण सावधानी से किया जाना चाहिए।" भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

भारतीय संविधान का अनु. 142, न्यायपालिका को प्राप्त विवेकाधिकार से संबंधित है, जिसका प्रयोग "संपूर्ण न्याय" (complete justice) स्थापित करने के लिए किया जाता है।

A.142 से असाधारण शक्तियाँ

1. A.142 के संबंध में संविधान में स्पष्ट परिभाषा व प्रयोजन की सीमाओं का अभाव है।
2. अतः इसका प्रयोग विवेकाधीन
3. शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत (A.50) को भी पार कर सकती है (eg विशाखा दिशानिर्देश, प्रकाशसिंह बाद वाद कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है।
4. यह इन मामलों में उपयोग की जाती है

जिसका प्रभाव व्यापक होता है। Eg चंडीगढ़ मेयर चुनाव में प्रयोग।

6. संविधान में विधानमंडल की कार्यवाही पर न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित किया गया किंतु न्याय व लोकतंत्र स्थापित करने के लिए प्रयोग Eg किहोतो होलोहान वाद

असाधारण सावधानी की आवश्यकता।

1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को न्यायिक संप्रभुता में बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए Eg NJAC वाद

2. विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना → दो सिद्धांत

- प्रतिनिधिक लोकतंत्र
- शक्तियों का पृथक्करण

हालांकि न्यायपालिका द्वारा व्यापक जनहित तथा न्याय को प्रतिस्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे न्यायिक विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।

Feedback
(For OFFICE use only)

#	Ⓖ	Ⓐ	Ⓟ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

Q.2) Why are State Legislative Assemblies involved in the election of the President but excluded from the process of impeachment? (10 marks, 150 words)

राज्य विधान सभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा जाता है? (10 अंक, 150 शब्द)

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान A-61 से प्राप्त होता है तथा यह अप्रत्यक्ष और आनुपातिक मतदान पद्धति पर आधारित होता है।

विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया जाना

1. राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में विधानसभा सदस्यों की आनुपातिक ताकि [गणतांत्रिक चुनाव] अधिक प्रतिनिधिमूलक बने।
2. विधानसभा सदस्य कुल जनता का प्रतिनिधित्व करती है और संख्या में अपेक्षाकृत (~5000) अतः सभी के मतों को राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी मिलती है।

3. इसमें भी विधानपरिषद के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वह अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित और सभी राज्यों में स्थापित नहीं।

महाभियोग प्रक्रिया से बाहर रखा जाना।

1. प्रक्रिया के सरलीकरण करने के लिए

2. तकनीकी कारणों से :- यदि संसद द्वारा राष्ट्रपति को अविश्वास तो यह माना जा सकता कि वर्तमान स्थिति में राष्ट्रपति पूर्ण बहुमत / विश्वास की स्थिति में नहीं है।

3. मानवसंसाधन की आवश्यकता और चुनावी मशीनरी पर बल।

4. संसद द्वारा भी महाभियोग में 2/3 मतों तथा कुल सदस्यों के 50% से अधिक के मतदान की आवश्यकता।

5. राज्यसभा द्वारा राज्यों का प्रतिनिधित्व शामिल रखा है।

इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव व महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र को गणतंत्र बनाता है

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Feedback (For OFFICE use only)
Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.
TOTAL MARKS

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

Q.3) Private Member's Bills (PMBs) seldom become law in India, yet they are an important aspect of parliamentary democracy. Bring out their significance and suggest steps to strengthen the PMB process. (10 marks, 150 words)

भारत में निजी सदस्य विधेयक (PMBs) शायद ही कभी कानून बनते हैं, फिर भी वे संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। उनके महत्व को उजागर करें और निजी सदस्य विधेयक प्रक्रिया को सशक्त करने के लिए उपाय सुझाएँ। (10 अंक, 150 शब्द)

भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा पेश की गयी विधेयक को निजी सदस्य विधेयक (PMBs) के रूप में जाना जाता है।

शायद ही कभी कानून बनते हैं:—

→ आजतक के इतिहास में केवल 17 विधेयकों पर ही चर्चा व पारित हो पायी है।

संसदीय लोकतंत्र में महत्व

1. विधायिका के दायित्वों का निर्वहन
   → कानून निर्मात्री संस्था और सदस्यों
2. स्थानीय मांगों का प्रतिनिधित्व
3. अल्पमत के हितों का प्रतिनिधित्व

तथा लोकप्रिय अनैतिक मतों के खंडन में उपयोगी।

7. संसदीय उत्पादकता और संसदीय भागीदारी को बढ़ाता है।

8. PMBs के माध्यम से विपक्ष द्वारा वैकल्पिक विधान प्रदान करना।

9. संशोधनों को पेश कर कानून में सुधार।

PMBs को सफल करने के उपाय

- स्थायी आदेशों की लचीलेपन की आवश्यकता
  - RS, LS सभापति की निष्पक्षता
- PMBs के निर्माण में विभागीय संसदीय समिति का योगदान
- संसद सत्र में PMBs के लिए विशेष दिनों का आवंटन

इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति में सुधार कर प्रतिनिधित्व को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

Feedback
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

Q.4) Highlight the key points of convergence and divergence between the judicial systems of India and USA. (10 marks, 150 words)

भारत और अमेरिका की न्यायिक प्रणालियों के बीच अभिसरण और विचलन के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। (10 अंक, 150 शब्द)

आधुनिक युग में अमेरिका सबसे पुराना संविधान आधारित लोकतंत्र है वहीं भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में चेक और बैलेंस के सिद्धांत को स्थापित करने दोनों स्थानों के न्यायपालिका की भूमिका है।

IND-USA: न्यायपालिका में विचलन

भारत	USA
1. भारत में संघीय न्यायालय के जगह एकीकृत न्यायालय व्यवस्था	1. संघीय न्यायालय तथा राज्यों का स्वतंत्र न्यायालय
2. SC के भीतर ही संविधानपीठ	2. सर्वोच्च न्यायालय केवल संवैधानिक

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

	मामलों की जाँच
3. संविधान से न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं	3. न्यायिक समीक्षा व पुनरावलोकन
4. "कानून की स्थापित प्रक्रिया" (Procedure established)	4. "नीतिगत प्रक्रिया" (Due Process)
5. संघीय विवाद की न्यायालय	5. संघीय विवाद को स्थान नहीं
6. 142 से संपूर्ण न्याय	— यह अनुपस्थित

अभिसरण के बिंदु

भारत	USA
1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोनों स्थानों में	
2. राष्ट्रपति के चुनावों पर दोनों न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार	
3. शक्ति के पृथक्करण की उपस्थिति दोनों स्थानों में	

Feedback
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

इस प्रकार न्यायपालिका का संविधानिक संस्थाकरण लोकतंत्र का आधार मानी है

Q.5) The role of Election Commission of India has evolved beyond conducting elections to becoming a guardian of electoral democracy. Critically evaluate. (10 marks, 150 words)

भारत के चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव कराने से आगे बढ़कर चुनावी लोकतंत्र के संरक्षक बनने तक विकसित हो गई है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (10 अंक, 150 शब्द)

भारतीय संविधान के A-324 के तहत चुनाव आयोग को अधिकार व दायित्व सौंपे गये जिससे "मुक्त और निष्पक्ष चुनाव" सुनिश्चित किया जाता है।

EC के चुनावी दायित्व
- आम-चुनावों का आयोजन
  - A. लोकसभा, B. विधानसभा
- उपचुनाव का आयोजन
  - A. राष्ट्रपति; B. राज्यसभा, C. विधानपरिषद

लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी

1) फ्री और फेयर चुनाव: मूल ढाँचे का हिस्सा तथा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी
2) PUCL वाद तथा नोटावाद

2. जनता में जागरूकता → SVEEP के माध्यम से मतदाता दरों में वृद्धि के प्रयास

3. मतदाता प्रमाणपत्रों की सत्यापन तथा प्रवासिय भारतीयों को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करना → 37० भारतीय प्रवासी

4. आचार संहिता (CoC) लागू कराना, घृणात्मक भाषणों (hate speech) पर रोक लगाना → RPA 1951 – sec 125

5. चुनावों में तकनीक का प्रयोग और पारदर्शिता वृद्धि करना → VVPAT का प्रयोग

6. चुनाव विवादों की सुनवाई व अर्धन्यायिक भूमिका।

7. संसद अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना।

8. चुनाव में अंतरविभागीय समन्वय → सुरक्षा बलों का नियोजन

Feedback
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

हालांकि, पारदर्शिता में वृद्धि, मानव संसाधन की आवश्यकता, निष्पक्ष प्रक्रिया में वास्तविकता से

Q.6) What is the rationale behind the 'three-language formula' in India's education policy? Also highlight the challenges associated with its adoption and implementation across the country.

(10 marks, 150 words)

भारत की शिक्षा नीति में 'त्रि-भाषा सूत्र' के पीछे क्या तर्क है? देश भर में इसे अपनाने और लागू करने से जुड़ी चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें।

(10 अंक, 150 शब्द)

नशिक्षा नीति 2020 में कस्तुरिरंगन समिति के सिफारिशों के अनुरूप 'त्रिभाषा सूत्र' को अपनाया गया।

त्रिभाषा सूत्र → प्राथमिक पाठ्यक्रम में तीन भाषाओं का चयन

- स्थानीय भाषा eg. मलायलम, तमिल, बांग्ला
- अंतर स्थानीय भाषा/राष्ट्रीय eg. हिन्दी
- सार्वभौमिक भाषा eg. अंग्रेजी

त्रिभाषा सूत्र के पीछे तर्क

1. भाषायी एकता और विविधता का संरक्षण।
2. प्रवासी गतिशीलता में वृद्धि तथा

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

आजीविका व संरक्षण की स्वतंत्रता (A. 19(1)) को उचित क्रियान्वयन।

3. भाषायी हीनता (अंग्रेजी आधारित) को समाप्त करने का प्रयास।

4. राष्ट्रीय भाषा के विकास का प्रयास।

5. बच्चों के बहुआयामी विकास में सहायक।

अपनाने - लागू करने में चुनौतियाँ

1. क्षेत्रवादी चुनौती
   - A. दक्षिणी राज्यों का आरोप → हिन्दी इंपोजीशन का
   - B. भाषायी संवेदनशीलता eg. मराठी मानुस (सिद्धां)

2. तकनीकी चुनौती
   - A. तीन भाषाओं में पाठ्यक्रम
   - B. शिक्षकों के स्तर की अनुपलब्धि
   - C. सार्वभौमिकता का अभाव अत: विभिन्न भाषाओं का प्रयोग

Feedback (For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS

3. उत्तरी राज्यों द्वारा दक्षिणी भाषाओं के स्थान पर संस्कृत को स्थान देना eg. UP

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

Q.7) 'Emerging environmental concerns and evolving ecosystem perspectives demand a reimagined approach to rural water governance.' Discuss the key interventions needed to recalibrate rural water policies with special emphasis on the role of communities. (10 marks, 150 words)

'उभरती पर्यावरणीय चिंताएँ और विकसित होते पारिस्थितिकी तंत्र के परिप्रेक्ष्य ग्रामीण जल प्रशासन के लिए एक नए दृष्टिकोण की मांग करते हैं।' समुदायों की भूमिका पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण जल नीतियों को पुनः संतुलित करने के लिए आवश्यक प्रमुख हस्तक्षेपों पर चर्चा करें। (10 अंक, 150 शब्द)

भारत में भौमजल स्तर ~1400 q्m के स्तर पर है जो जलतनाव ~1700 q्m की सीमा को पार कर चुका है। अतः ऐसे में समाधान का दृष्टिकोण विकेंद्रीकृत करके वांछित उपाय किया जा सकता है।

समुदाय आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता।

1. मानवसंसाधन पूंजी के माध्यम से नवाचार व पर्यावरणीय पहलों में गति
   (e.g.) पीपलबाबा और टीम द्वारा पेड़ लगाकर भौमजल पुनर्भरण।
2. समुदाय आधार से स्थानीय समाधान
   (e.g.) राजस्थान में बावलियों का संरक्षण संभव

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

3. सामुदायिक दृष्टिकोण से आपसी जवाबदेही सुनिश्चित और क्षेत्रगतविविधता में संधारणीय सिंचाई पद्धति का प्रयोग (eg) FPO के माध्यम से ड्रीपसिंचाई।

4. महिला समुदायों की सहायता से जल सुरक्षा को उद्यम बनाना (eg) स्वयं सहायता समूह द्वारा जल सुरक्षा व आयअर्जन।

5. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोगी (eg) जलजीवनमिशन में ग्राम समिति का योगदान

6. समुदाय से हितधारकों की भागीदारी और जलयोजनाओं का भ्रष्टाचार क्षय (eg) अटल भूजल योजना का सामाजिक सर्वेक्षण

7. समुदाय में आय सृजन का माध्यम भी बनना (eg) मनरेगा के माध्यम से तालाब निर्माण

Feedback (For OFFICE use only)

#	Ⓖ	Ⓐ	Ⓟ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

इस प्रकार स्थानीय पद्धति व समुदाय की भागीदारी से जल संकट का

Q.8) Identify and discuss the challenges hindering effective implementation of gender-sensitive policies and schemes in the country. (10 marks, 150 words)

देश में लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली चुनौतियों की पहचान करें और उन पर चर्चा करें। (10 अंक, 150 शब्द)

संविधान की प्रस्तावना सामाजिक न्याय की प्रस्ताव करती है वहीं A.15-A.16 लैंगिक आधारों पर समानता के अधिकार प्रदान करती है, इसके बावजूद भारत में लैंगिक असमानता चुनौतीपूर्ण स्थिति में है :- (131st Rank GGG)

समलैंगिक: नालसा वाद; नवतेज जोहर वाद

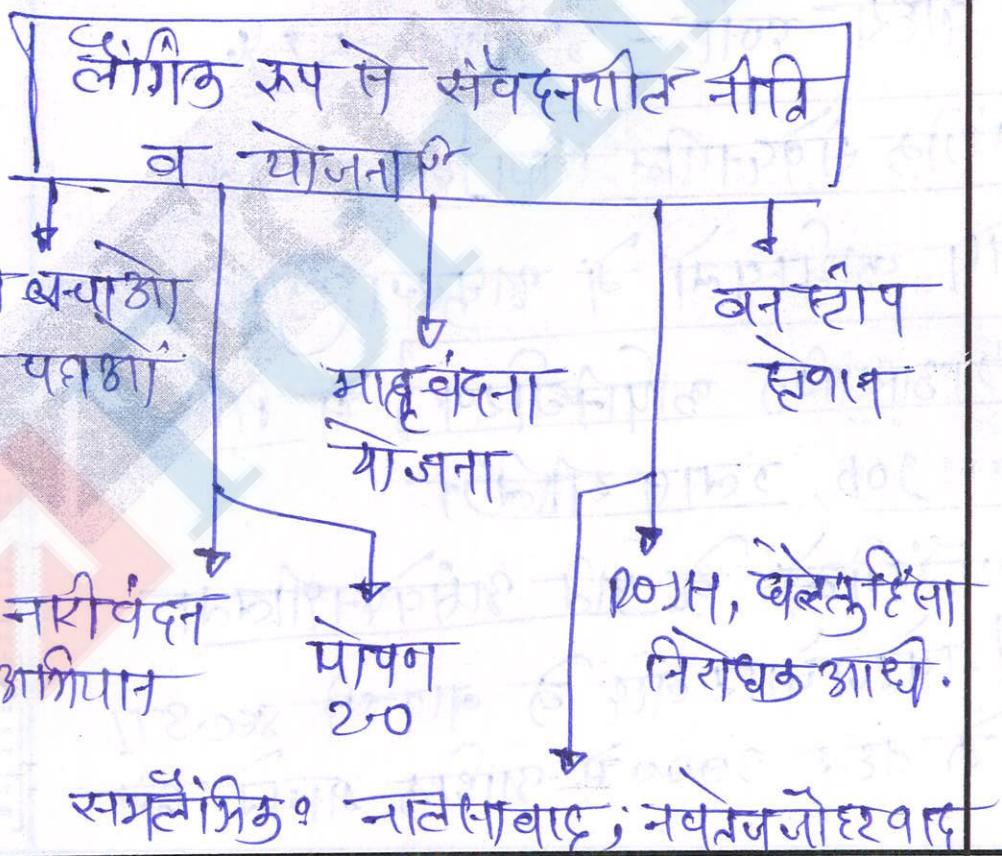

ForumIAS

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

नीति क्रियान्वयन में बाधा – चुनौतियाँ

1. बजट बजटीय आवंटन का केवल प्रचार में प्रयोग (ex) BBBP में 85% व्यय प्रचार पर

2. सामाजिक पितृसत्तात्मक (ex) पंचायतों के स्तर पर सरपंचपति की संकल्पना।

3. केवल नामित मुखिया, शासनकार्य धारक महिला किंतु महिलाओं के शोषण को ही दोहरा दर्जा – अतिक्रिया – 5%

4. लैंगिक संवेदनशील शिक्षा का अभाव, जिससे कार्यस्थलों में असुरक्षा (ex) सेक्सुअल हैरेसमेंट

5. लैंगिक आधारित कार्यनिर्धारण से Pink collar job, ग्लास सीलिंग

6. सम लैंगिकों के प्रति असंवेदनशीलता (ex) नवतेज जौहर वाद के बाद भी 377 के तहत 3000 से अधिक मामले दर्ज

Feedback (For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

अतः इन चुनौती समाधान में SDG 5 की प्राप्ति का प्रयास

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

Q.9) Effective transboundary water management can act as a catalyst for regional peace and cooperation.' In light of this statement, bring out the opportunities and challenges for India in leveraging 'water diplomacy' in its neighbourhood. (10 marks, 150 words)

प्रभावी सीमापार जल प्रबंधन क्षेत्रीय शांति और सहयोग के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है।' इस कथन के आलोक में, भारत के लिए अपने पड़ोस में 'जल कूटनीति' का लाभ उठाने के अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। (10 अंक, 150 शब्द)

21वीं सदी में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है तथा इसकी रणनीतिक महत्ता को बताते हुए वाजपेयी जी ने कहा था कि जल की समस्या तीसरे विश्वयुद्ध का कारण बनेगी।

अतः जल समस्या का प्रबंधन व समाधान क्षेत्रीय शांति का प्रेरक हो सकती है।

जल कूटनीति के लाभ उठाने का अवसर

1. बांग्लादेश से सामाजिक कूटनीति
   1. तीस्ता जल विवादों के समाधान से आपसी सहयोग में वृद्धि।
   2. गंगा नदी के माध्यम से नौपरिवहन

में ब्राह्मी से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना (अभी ~$18B)

C. उत्तरपूर्वी संपर्क को बढ़ाने में बराक नदी आधारित समझौते का प्रयोग करना।

2. नेपाल से कूटनीतिक अवसर

A. कोसी नदी बाढ़ की समस्या का समाधान संभव

3. नेपाल व भूटान में भारत की जल परियोजना से ऊर्जा सुरक्षा व जल सुरक्षा।

4. म्यानमार में सित्वे पोर्ट निर्माण तथा कालादान प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय शक्ति का बढ़ना।

जल कूटनीति की चुनौतियाँ

1. चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र पर विशाल बांध का निर्माण व जानकारी साझा न करना।

2. पाकिस्तान सिंधु नदी संधि के संशोधन की चुनौती।

3. कालीनदी तथा नेपाल से सीमा पर तनाव।

Feedback
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

Q.10) What are the key areas of reform if the World Trade Organization (WTO) has to remain relevant in the present context of rising protectionism and trade wars? (10 marks, 150 words)

यदि विश्व व्यापार संगठन (WTO) को बढ़ते संरक्षणवाद और व्यापार युद्धों के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक बने रहना है तो सुधार के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? (10 अंक, 150 शब्द)

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा WTO से अपनी सदस्यता वापसी की धमकी दी गयी जो WTO की प्रासंगिकता पर प्रश्न आरोपित करता है।

संरक्षणवाद और व्यापार युद्धों में प्रासंगिकता का संकट

1. राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ज्यादातर देशों में टैरिफ की धमकी
   (a) जापान और EU पर 25% टैरिफ आरोपित।
2. चीन द्वारा अपनी कंपनियों को निर्णय कि बिना अनुमति के क्रिटिकल कंपनियों का निर्यात नहीं।

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

3. फ्रेंडशोरिंग के माध्यम से इकोनॉमिक डीकपलिंग।

4. अपीलीय निकाय का निष्क्रिय रहना।

सुधार की आवश्यकता

1. एक पक्षीय व्यापार कार्यवाहियों पर WTO द्वारा कार्यवाही करना।
2. विश्वसनीयता बढ़ाना : चीन के अवैध, अविनियमित (IUU) मत्स्यग्रहण पर कार्यवाही करें।
3. अपीलीय निकाय में पुनः स्थायी नियुक्ति की आवश्यकता।
4. वित्तपोषण के लिए विकासशील देशों से सहायता तथा क्राउडफंडिंग।
5. IT उत्पादों पर नये नियमों की आवश्यकता।
6. कृषि क्षेत्र संबंधी विषयों पर विकासशील देशों को सुरक्षा

WTO को पारदर्शिता के माध्यम से

Feedback
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

Q.11) The basic structure doctrine acts as a constitutional compass in balancing Parliament's legislative authority and constitutional supremacy. Comment. (15 marks, 250 words)

आधारभूत संरचना सिद्धांत संसद की विधायी शक्ति और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन बनाने में एक संवैधानिक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। टिप्पणी करें। (15 अंक, 250 शब्द)

केशवानंद भारती वाद के माध्यम से आधारभूत संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया।

आधारभूत संरचना संविधान की वे मूल विशेषताएं हैं, जिन्हें संसद परिवर्तित या संशोधित नहीं कर सकती।

(Eg) केशवानंद भारती वाद : न्यायिक समीक्षा
नोटा वाद : फ्री व फेयर चुनाव
MC मेहता वाद : पर्यावरणीय नैतिकता
→ पंथनिरपेक्षता, संघीय ढांचा आदि

विधायी शक्ति व संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच संतुलनकारी

1. यह सिद्धांत विधायी शक्ति को

बनाए रखता है—

A. A-368 के तहत संविधान संशोधन का विधायी अधिकार

B. शंकरी प्रसाद वाद में मौलिक अधिकारों को सीमित करने में संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक माना था किंतु इसे स्वीकार किया गया।

C. यह निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है।

(e) मिनर्वा मिल्स वाद : DPSP व FR में तार्किक संतुलन।

D. विभिन्न संशोधन भी किये गये:-

(e) 106th CAA से नारी वंदन योजना
~~103~~ 103rd EWS आरक्षण प्रावधान

20 यह संवैधानिक सर्वोच्चता को भी बनाए रखता है -

A. मूलढाँचे को प्रभावित करने वाले मामलों पर कार्यवाही

(eg) उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का अतार्किक आरोपण संघीय ढाँचे के विपरीत

→ वहीं 99th CAA में राज्यों की सहमति नहीं होने से राज्यों पर लागू नियमों को Readdown.

B. प्राण व दैहिक स्वतंत्रता (मूलढाँचे) का विस्तार (A.21)

(eg) SC MK रणजीत सिंह वाद - पर्यावरणीय/जलवायु कार्यवाही का अधिकार (A.21)

यह सिद्धांत संविधान को जीवंत और प्रासंगिक बनाता है

Feedback (For OFFICE use only)			
#	Ⓖ	Ⓐ	Ⓟ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			
Please put tick marks in the above table. Here G is Good, A is Average and P is Poor.			
TOTAL MARKS			

किंतु साथ ही यह न्यायपालिका को असीमित शक्ति देता है जिसका प्रयोग न्यायिक संयम के साथ करना चाहिए।

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

Q.12) Urban Local Bodies (ULBs) are pivotal to inclusive and efficient urban governance, yet they remain fiscally constrained and institutionally weak. Analyze. (15 marks, 250 words)

शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) समावेशी और कुशल शहरी शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं, फिर भी वे वित्तीय रूप से सीमित और संस्थागत रूप से कमज़ोर बने हुए हैं। विश्लेषण करें। (15 अंक, 250 शब्द)

74th CAA के माध्यम से 12वें अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों को स्थान दिया गया और शासन का विकेंद्रीकरण किया गया।

ULBs समावेशी व कुशल शहरी शासन के लिए महत्वपूर्ण

कुशलता

1. प्रतिनिधी आधारित चुनाव प्रणाली से लोकतंत्र का प्रत्यक्षीकरण
2. स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान (e) अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी शहरी निकायों को
3. शहरी संपत्ति कर के माध्यम से आय (e) बाम्बे शहरी निकाय सबसे बड़ा बजट

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

4. प्रतिनिधियों से जवाबदेही तय करना

[eg] वार्ड समिति के माध्यम से जवाबदेही।

~~6. शहरी~~

समावेशिता

1. आरक्षण लागू
   - → महिला आरक्षण 1/3
   - → SC/ST आरक्षण जनसंख्या अनुरूप

2. लैंगिक बजट के माध्यम से नारी सुरक्षा केंद्रों की स्थापना [eg] रायपुर नगि.

3. झुग्गी बस्तियों का विकास करना

4. स्मार्ट सीटी परियोजना के तहत रोजगार से समावेशिता।

इसके बावजूद वित्तीय रूप से सीमित

1. संविधान द्वारा घोषित 18 अधिकारों को राज्य द्वारा हस्तांतरण नहीं

2. कर आरोपण आधार सीमित तथा अप्रासंगिक अधिकार [eg] चारा कर

3. राष्ट्रीय अनुदानों तथा राज्य की योजनाओं पर आश्रित (eg) PM आवास शहरी, 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 4.35 लाख Cr अनुदान

[संस्थागत रूप से कमजोर]

1. मानव संसाधन के प्रति स्वायत्तता नहीं
2. नगरीय CEO का प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह न होना।
3. तकनीक के अभाव से क्रियान्वयन कमजोरी।

अतः ARC II के Report

→ कर्मचारी आधारित स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता।

→ राज्यों द्वारा केरल के विपुल स्थान के समान अधिकारों का हस्तांतरण।

→ [नीति आयोग] के माध्यम से तकनीक आधारित क्षमता निर्माण।

इस प्रकार शासन का विकेंद्रीकरण का वास्तविक

Feedback
(For OFFICE use only)

#	Ⓖ	Ⓐ	Ⓟ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

Q.13) "The judiciary has functioned as an institutional corrective, redefining and refining the contours of the Governor's office to prevent its misuse and uphold constitutional principles." Discuss this statement with the help of relevant case laws. (15 marks, 250 words)

"न्यायपालिका ने एक संस्थागत सुधारक के रूप में कार्य किया है तथा राज्यपाल के कार्यालय की रूपरेखा को पुनः परिभाषित और परिष्कृत किया है ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके और संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखा जा सके।" प्रासंगिक न्याय विधियों (केस लॉ) की मदद से इस कथन पर चर्चा करें। (15 अंक, 250 शब्द)

राज्यपाल का पद भारत में राज्यों तथा संघ के बीच सेतु निर्माण के लिए नामित प्रतिनिधि के तौर पर किया गया है हालांकि इस पद के दुरुपयोग से यह केंद्र के एजेंट की भाँति नजर आती है।

न्यायपालिका द्वारा संस्थागत सुधार

1. पंजाब बनाम UOI व तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल वाद (2025) में राज्यपाल के वीटो अधिकार (A 200) को सीमित किया गया।

A. इसके तहत निलंबनकारी वीटो की

समयसीमा तय की गयी तथा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के विषय में 3माह का समय निर्धारित

2. नबामरेबिया वाद : में राज्यपाल के राष्ट्रपति शासन की अधिघोषणा तथा बहुमत के निर्धारण के आधार को सीमित किया गया।

→ बहुमत का निर्धारण सदन के पटल पर।

3. समशेरसिंह वाद में कहा गया कि राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन नियोजन/रोजगार नहीं है।

4. बिहारराज्यपाल वाद में निर्धारित किया गया कि अध्यादेशों (A-2013) का प्रयोग विधायिका के समानांतर अधिकारों

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

के रूप में नहीं किया जा सकता।

6. दिल्ली LG वाद : निर्वाचित सरकार की सिफारिशों के अनुरूप कार्यसंचालन।

6. SR बोम्मई वाद में संघीय ढांचे को तथा पंथनिरपेक्षता को आधारभूत ढांचे का हिस्सा बताया गया।

इस प्रकार राज्यपाल के पद को राजनीतिक उपकरण होने से बचाया गया। क्योंकि इसमें सुधार

1. पुंछीआयोग की सिफारिशों के अनुरूप 5वर्ष का निश्चित कार्यकाल तथा राज्यविधान सभा द्वारा महाभियोग।

2. सरकारिया आयोग : राज्यों से सहमति के आधार पर नियुक्ति।

राज्यपाल के पद का गैरराजनीतिक प्रयोग राज्यों की स्वायत्ता व संघीय ढांचे के अनुरूप होगा।

Feedback
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

Q.14) How is the 'vertical' and 'horizontal' devolution of taxes to the states decided? Highlighting the concerns raised by some states regarding the devolution of taxes, suggest corrective measures.
(15 marks, 250 words)

राज्यों को करों का 'ऊर्ध्वाधर' और 'क्षैतिज' हस्तांतरण कैसे तय किया जाता है? करों के हस्तांतरण के संबंध में कुछ राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए सुधारात्मक उपाय सुझाएँ।
(15 अंक, 250 शब्द)

अनु॰ 280 के प्रयोग के माध्यम से वित्त आयोग की स्थापना की जाती है जिसे करों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के सिद्धांत निर्माण का दायित्व दिया जाता है।

राज्यों को करों का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण

1. केंद्र के राजस्व आय का आकलन
2. इसमें सेस व सरचार्ज की गणना नहीं।
3. राज्यों की आवश्यकताओं व लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्ध्वाधर सूत्र
   (eg) 14th FC : 42%, 15th FC : 41%
4. 1% की कटौती लद्दाख व JnK UTs

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

के आधार पर।

क्षैतिज हस्तांतरण

1. विभिन्न आधारों की तुलना
   - आय असमानता (45% भार)
   - जनसंख्या (2011 : 15th FC)
   - वन व पारिस्थितिकीय (10% भारित)
   - शासन प्रदर्शन (5%)

2. अंतरापीढ़ीगत न्याय के सिद्धांतों पर आधारित

→ वितरणमूलक न्याय

(eg)	सहयोग	प्राप्ति
बिहार	₹1	₹1
TN	₹1	₹0.27

3. संघीय संरचना के अनुरूप

करों के हस्तांतरण में चिंता

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

1. दक्षिणी राज्यों को हानि की चिंता
  - आर्थिक सहयोग कम प्राप्ति
  - जनसंख्या कार्यवाही किंतु 2011 जनगणना को आधार बनाना।
2. राज्यों से सलाह-सिफारिश नहीं
3. सेस व सरचार्ज को शामिल नहीं किया जाना
  - कुल सकल राजस्व का 20%
4. स्वैच्छिक अनुदान का घटना
  - 2016: 1.92 लाख cr
  - 2023 - 1.6 लाख cr
5. शासन प्रदर्शन को आधार बनाने से पिछड़े राज्यों को और हानि।

अतः FC में सुधार की आवश्यकता है-

1. संघीय विचारविमर्श के माध्यम से सिद्धांत
2. सेस-सरचार्ज को हिस्सा बनाना।
3. ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण 50% करना क्योंकि राज्यों को दायित्व अधिक

Feedback
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.
TOTAL MARKS

4. सिफारिश बाध्यकारी बनाना।

इसके माध्यम से वित्तीय सुशासन

Q.15) What steps are required for the constitutionalization of a Commission? Do you think granting constitutional status to the Central Information Commission (CIC) would strengthen the RTI regime in India? Give reasons. (15 marks, 250 words)

किसी आयोग के संवैधानिककरण के लिए क्या क़दम उठाने की आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को संवैधानिक दर्जा देने से भारत में RTI व्यवस्था मजबूत होगी? कारण बताइए। (15 अंक, 250 शब्द)

भारत में संविधानिक संस्थाओं की उपलब्धि है जो इसे अधिक स्वायत्ता व दायित्वों का विस्तार करती है।

eg NCSC, NCST (A-338, A-338A)

आयोग के संवैधानिकरण के उदम

1. संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा
   eg 102nd CAA से NCBC को संवैधानिक दर्जा।
2. अधिक स्वायत्ता तथा दीवानी न्यायालय की शक्ति प्रदान।
3. वित्तीय दायित्वों को भारित व्यय का

हिस्सा बनाना।

4. नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

5. पदसोपान में बदलाव

सूचना आयोग एक कानूनी संस्था है, तथा पारदर्शिता स्थापित करने की निकाय है।

इसके संवैधानिकरण से लाभ

1. नियुक्ति संबंधी राजनीतिक हस्तक्षेप घटेगा।
2. पेंडिंग RTI मामलों (3 लाख से अधिक) के निस्तारण में कानूनी अड़चनें।
3. सरकार के विभिन्न विभागों को आदेश जारी करने का अधिकार

4. तकनीकि के बेहतर प्रयोग से RTI संबंधी अनुक्रियाशीलता में वृद्धि।

8. संरचनात्मक त्रुटि का समाधान, वस्तुतः CIC वैधानिक संस्था होते हुए भी CJI कार्यालय, UPSC, CAG आदि संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करता है, जो कि विरोधाभासी है।

अतः सुधार आवश्यक है किंतु संवैधानिक दर्जा देना पर्याप्त नहीं है — क्योंकि NCSC संवैधानिक निकाय होते हुए भी निष्क्रियता का आरोप। साथ ही कार्यालय, वेतन की सुरक्षा, ओम्बुड्समैन व्यवस्था, तथा सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति को बाधित करने की आवश्यकता है।

Q.16) Even as India experiences consistent economic growth and has achieved self-sufficiency in food production, hunger and food insecurity remain pressing concerns. Examine the factors responsible for this paradox and suggest steps to improve the situation. (15 marks, 250 words)

भारत में भले ही लगातार आर्थिक संवृद्धि हो रही है और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल हो गई है, लेकिन भूख और खाद्य असुरक्षा अभी भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस विरोधाभास के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण करें और स्थिति को सुधारने के लिए कदम सुझाएँ। (15 अंक, 250 शब्द)

भारत सबसे तेजी से संवृद्धि करता विशाल अर्थव्यवस्था है (6% GR के साथ 4वी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था) इसके बावजूद भी लगभग 80 Cr आबादी PDS प्रणाली पर निर्भर है।

विरोधाभास के उत्तरदायी कारक

1. **जनसंख्या वृद्धि** : 1.5 अरब लोगों के साथ सबसे विशाल आबादी (2025)
2. **आय असमानता** की उच्चता से **क्रयक्षमता बाधित** (eg) 1% आबादी के पास 39% संपत्ति (Oxfam)

4. हेडलाइन मुद्रास्फीति का उच्च स्तर में बने रहना। (उ) 2021 के बाद से औसतन 6% से अधिक (CPI)

5. अल्परोजगार व प्रछन्न बेरोजगारी से पोषण व्यय की कमी (उ) मनरेगा दैनिक मजदूरी आज भी ₹150 से ऊपर नहीं

6. उत्पादन आधारित समस्या

A. एकफसलीय उत्पादन से पोषण का विविधीकरण नहीं

(उ) धान-गेहूं पद्धति से कुन्दन का (खाद्य अनाज) बनना।

B. भंडारण क्षमता की कमजोरी से लगभग प्रतिवर्ष ₹92000 करोड़ का नुकसान।

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

6. खाद्य सुरक्षा किंतु पोषण असुरक्षा

A. महिलाओं में 57% एनीमिया व 50% आयरन की कमी (son meta preference के कारण)

B. बच्चों में 37% स्टंटिंग व 19% वास्टिंग।

स्थिति सुधारने के कदम

1. पोषण सुरक्षा को महत्व

A. उत्पाद आधारित सुरक्षा – उच्च प्रोटीन मात्रा

2. पोषण 2.0 के तहत चना व अन्य नये उच्च पोषक तत्वों को स्थान।

3. PM ईश्रम योजना से श्रमिकों को जोड़ना व रोजगार सघनता बढ़ाना।

4. श्रम संहिताओं के उचित क्रियान्वयन से सामाजिक सुरक्षा तय करना।

Feedback
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

5. आवश्यक वस्तुओं पर GST की दर कम करना

साथ ही मौद्रिक नीति के प्रयासों

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

Q.17) The Union Government has recently announced that caste enumeration will be part of the upcoming census. Examine the opportunities and challenges associated with conducting a nationwide 'caste census'. Also, propose a framework for its seamless and effective conduct.

(15 marks, 250 words)

केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि जाति गणना आगामी जनगणना का हिस्सा होगी। राष्ट्रव्यापी 'जाति जनगणना' आयोजित करने से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण करें। साथ ही, इसके निर्बाध और प्रभावी संचालन के लिए एक रूपरेखा को प्रस्तुत करें।

(15 अंक, 250 शब्द)

2027 में आयोजित जनगणना को जाति आधारित जनगणना के तर्ज पर किया जाने का निर्णय है, जोकि सामाजिक न्याय की एक पहल है।

जाति जनगणना आयोजन के अवसर

1. डेटा से रुझान के सिद्धांतों का अनुपालन
   - उचित डेटा से कल्याणकारी योजनाओं का उचित लक्ष्यीकरण।
2. सब्सिडी का तार्किकरण संभव होगा तथा राजकोषीय व्यय से राजकोषीय विवेक की स्थापना होगी।

3. जाति आधारित भेदभाव के प्रति कार्यवाही में तेजी तथा सामाजिक समानता से सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण।

4. निर्धनता उन्मूलन में तेजी, क्योंकि अनुमानतः 90% गरीब पिछड़े वर्गों से।

5. जाति के भीतर जाति आधारित असमानता की कमी का उपकरण
(E) दविंदर सिंह वाद के अनुरूप उपवर्गीकरण में सहायक

जातिजनगणना की चुनौतियां

1. जातिआधारित भेदभाव व पहचान आधारित राजनीति से विकास बाधित होने का भय।

2. आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग तेज हो सकती है जोकि

इंदिरा साहनी वाद में 50% तक सीमित है।

3. जातिजनगणना में 47000 अधिक जाति इसकी पहचान की चुनौती।

4. निजता का मुद्दा और गलत जानकारी के भय से विकृत जनगणना का खतरा।

प्रभावी संचालन की रूपरेखा

1. आयोग की स्थापना : जातियों व उपजातियों के पहचान के निश्चित ढांचा निर्माण के लिए।
2. जी. रोहिणी समिति के आकलन का प्रयोग करना।
3. राज्य आधारित सहयोग की आवश्यकता व संघीय सहकारिता
4. डिजिटल माध्यमों से जनगणना की पारदर्शिता
5. उचित प्रशिक्षण आधारित कर्मियों का निर्माण।

इन प्रयोगों से आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय और सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकता है।

Feedback
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

Q.18) "AI integration in governance is no longer a choice but a necessity." In light of this statement, discuss how AI can enhance education and healthcare governance. (15 marks, 250 words)

"शासन में AI का एकीकरण अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है।" इस कथन के आलोक में, चर्चा करें कि AI किस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शासन को बढ़ा सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त निर्णय प्रणाली व पैटर्न रिकग्निशन तंत्र है जो ChatGPT, Gemini, Deepseek, Xai आदि के माध्यम से लोकप्रिय हो रहा है।

विकल्प नहीं आवश्यकता है

1. यह शासन में तेजी व अनुक्रियाशीलता लाएगा, जिससे लालफीताशाही घटेगी।

2. AI के ~~शासन में~~ शासन में प्रयोग से शासन की जानकारी का सार्वभौमीकरण होगा
→ जागरूक व सशक्त जनता निर्माण।

3. AI से अस्पष्टता में गिरावट व पॉलिसी पैरालिसिस को कम

किया जा सकता है साथ डिलिवरी डिफ़ेसिट को घटाया जा सकता है।

4. पारदर्शिता स्थापना में सहयोगी।

8. रिपिटेटिव कार्यों का हस्तांतरण।

शिक्षा शासन में AI का प्रयोग

1. कैरियर गाइडेंस का माध्यम हो सकता ताकि पेशागत भटकाव न हो
(e) इंजीनियरिंग आधारित वृहद आबादी

2. अनुवादक की भूमिका से भाषायी अवरोध की समाप्ति (e) भाषिनी एप

3. पाठ्यक्रमों को इंटरैक्टिव बनाने में तथा इंफोग्राफिक्स बनाने में

5. टेली-एजुकेशन के विस्तार में सहयोगी।

8. लैंगिक व भावनात्मक चिंता के प्रसार में।

स्वास्थ्य क्षेत्र में AI

1. रोग के पूर्व पहचान से बीमारियों के प्रति निवारक उपाय।

2. बीमारी आधारित रोडमैप बनाने और क्षेत्रों के निर्धारण में, ~~विशेष~~ लक्षित आवंटन।

3. ड्रग डिलीवरी सिस्टम में प्रयोग।

4. AIIMS के साथ सहयोग कर चिकित्सा सलाहकार के रूप में AI का प्रयोग।

5. ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों चिकित्सों की कमी को पाटने में।

हालांकि, AI आधारित वायस कम करने, सूचना में हेलुसिनेशन कम कर तथा विकेंद्रीकृत कर इसे अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है।

Feedback
(For OFFICE use only)

#	G	A	P
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

Q.19) Providing a brief overview of the aims and objectives of BIMSTEC, explain its significance for India. (15 marks, 250 words)

बिम्सटेक के लक्ष्यों और उद्देश्यों का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करते हुए भारत के लिए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

बिम्सटेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया बीच सेतु तथा सहयोग के लिए एक बहुपक्षीय निकाय है।

सदस्य देश व मानचित्र →

बिम्सटेक के लक्ष्य व उद्देश्य

1. हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा व सहयोग (eg) IORA, SAGAR मिशन

2. आपदारोधी तंत्र विकास तथा आपदा राहत में सहायता (eg) ऑपरेशन मैत्री

3. तकनीक हस्तांतरण और लाभ-पहुँच हस्तांतरण (ABS) सिद्धांत का पालन। (eg) IRNSS

4. क्षेत्र में पर्यटन का विकास करना।

5. आतंकवाद से सुरक्षा सुनिश्चित करना। अपराध के लिए औपचारिक चार्टर जारी (2023)

भारत के लिए BIMSTEC का महत्व

1. पाकिस्तान (SAARC) संरचना का एक उत्पादक विकल्प।

2. हिंद प्रशांत क्षेत्र में "प्रथम सहायक" की भूमिका में होना तथा महाशक्ति बनने की आकांक्षा के अनुरूप।

3. द.पू. एशिया में व्यापार का विस्तार करना तथा कृषि क्षेत्रों को

स्थापित कर FTA समझौता करना।

4. क्षेत्र में शांति और विकास के लिए
(eg) बांग्लादेश में अशांति-सत्तापलट से सीमा सुरक्षा

5. मानवाधिकारों की रक्षा के लिए
(eg) बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू की सुरक्षा।

6. संपर्क सहकार व्यापार में तेजी के लिए (eg) कालादान प्रोजेक्ट, BBN I

7. क्षेत्र में आपसी सहयोग से दक्षिण एशिया की समस्या का समाधान
(eg) TB सर्वाधिक मामले।

8. सीमा समाधानों में सहायक।

साथ ही सहयोग व शांति के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत दक्षिणी विश्व का नेतृत्वकर्ता बन सकता है।

Feedback
(For OFFICE use only)

#	Ⓖ	Ⓐ	Ⓟ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

Q.20) India's approach to its relationship with China has evolved into what can be best described as 'competitive coexistence'. Discuss in light of recent developments. What should be the broad contours of India's future China policy? (15 marks, 250 words)

चीन के साथ अपने संबंधों के प्रति भारत का दृष्टिकोण 'प्रतिस्पर्धी सह-अस्तित्व' के रूप में विकसित हुआ है। हाल के घटनाक्रमों के आलोक में चर्चा करें। भारत की भविष्य की चीन नीति की व्यापक रूपरेखा क्या होनी चाहिए?

(15 अंक, 250 शब्द)

FORUM IAS

(Don't Write anything in this Area / इस स्थान पर कुछ न लिखें)

ForumIAS

Feedback

(For OFFICE use only)

#	Ⓖ	Ⓐ	Ⓟ
AWIS			
CD & VA			
S & F			
P & R			

Please put tick marks in the above table.
Here G is Good, A is Average and P is Poor.

TOTAL MARKS	

Mentor Feedback Questions

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

Test Goal

1 ..... ☐

.....

2 ..... ☐

.....

3 ..... ☐

.....

Outcomes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Marking Scheme

Mark	Good	Average	Below average
10 Marker	3.75 – 5.0	3.0 – 3.5	< 3.0
15 Marker	5.75 – 7.0	4.0 – 5.5	< 4.0
20 Marker	7.75 - 10	6 - 7.5	< 6
✔✔	Key / Relevant Point		
✖	Vague / Irrelevant		

* Subject to change without prior notice.

Availing Mentorship - Now made easy & seamless via mentorship.forumias.com

Dear Students,

You can now avail Mentorship in both online & offline mode seamlessly. All you need to do is login to below URL and pick up a date and time and your Mentorship is scheduled at the designated time.

Visit the URL https://mentorship.forumias.com or Scan the QR code

When must you seek mentorship? When you are unable to fully comprehend the directions given by the evaluator in the MGP copy. A Mentor will help you understand the nuiances of your evaluated MGP copy. He / She will also be able to make suggestions, if needed, on improvements that you could make.

If we are already doing well, a reinforcement from the Mentor will further assist us in following the right path. A Mentor may also be able to give valuable inputs with respect to time management, presentation, structure etc. He may recommend you clearly to work on content or may suggest you to take courses / read books in case he feels you lack content that may be quickly improved with a course at ForumIAS or elsewhere, or some study material.

To download topper's copies, visit the link https://blog.forumias.com/testimonials

CSE 2024 - Topper's Testimonials and Test Copies

CSE Rank 1 Shakti Dubey, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 4 Shah Margi Chirag, Testimonial Click Here
CSE Rank 6 Komal Punia, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 7 Aayushi Bansal, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 9 Aditya Vikram Agarwal, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 11 ETTABOYINA SAI SHIVANI, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 15 BANNA VENKATESH, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 16 MADHAV AGARWAL, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 17 SANSKRITI TRIVEDY, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 18 Saumya Mishra, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 19 Vibhor Bhardwaj, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 20 Trilok Singh, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 21 DIVYANK GUPTA, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 22 Riya Saini, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 26 SHIVANSH SUBHASH JAGADE, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 28 RISHABH CHOUDHARY, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 31 SHREYA TYAGI, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 33 ALFRED THOMAS, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 34 ABHI JAIN, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 38 ABHISHEK SHARMA, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 41 Sachin Basavaraj Guttur, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 43 AVDHIJA GUPTA, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 44 MUDITA BANSAL, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 45 MALAVIKA G NAIR, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 48 RITIKA RATH, Download MGP Copies + Testimonial Click Here
CSE Rank 50 ANKUR TRIPATHI, Download MGP Copies + Testimonial Click Here